

तीन दिवसीय 10-12 दिसम्बर, 2020 राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी
पूर्वाचल का सतत विकास: मुद्दे, रणनीति एवं भावी दिशा

सारांश

1. डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय व पूर्वाचल विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित "पूर्वाचल का सतत विकास: मुद्दे, रणनीति एवं भावी दिशा" विषयक राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी का मा. मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा शुभारंभ एवं उद्घाटन भाषण दिया।
2. डीडीयू कुलपति प्रो. राजेश सिंह ने मेगा सेमिनार की रूपरेखा प्रस्तुत की मेगा सेमिनार में पांच प्रमुख क्षेत्रों में नौ तकनीकी सत्र आयोजित किये गए। इसके साथ साथ करीब आठ विशेष सत्र आयोजित किये गए। कुल मिला कर करीब 60 सेशन आयोजित किये गए।
3. राष्ट्रीय वेबिनार एवं संगोष्ठी के बारे में बात करते हुए कुलपति प्रो. राजेश सिंह ने कहा कि यह वेबिनार 5 सेक्टरों में विभाजित है: प्राथमिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा जल क्षेत्र। इसके अलावा 4 विशेष सेक्टर की ग्रुप भी आयोजित की गई है। इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्पेशल ग्रुप फार डेवलपमेंट, बैंकर्स मीट तथा स्पेशल पैकेज फार पूर्वाचल शामिल है। इस राष्ट्रीय वेबिनार एवं संगोष्ठी में कुल 386 शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। 70 फुल पेपर तथा 204 एब्सट्रैक्ट शामिल हैं। संगोष्ठी में अनेक राष्ट्रीय/ अन्तराष्ट्रीय संस्थानों जैसे- हार्वर्ड विश्वविद्यालय, एम.आई.टी. यूनिवर्सिटी आफ मेरीलैण्ड, यूनिवर्सिटी आफ माउण्टगोमरी, जॉन हॉकिंग्स तथा अन्य अकादमिक संस्थाओं व यू.के., यू.एस.ए. सहित पाँच से अधिक देशों से शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। संगोष्ठी में हजार से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड से जोड़ा गया है।
4. सेमिनार में प्रतिभाग करने के लिये करीब 60 ऑनलाइन लिंक Generate किये गए। एक दिन में करीब 800 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन भाग लिया और करीब 300 लोगों ने ऑफ लाइन हिस्सा लिया। Zoom के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट भी किया गया जिसमें करीब 25,400 लोग जुड़े।
5. इस मेगावेबिनार की विशेष उपलब्धि इसका वैश्विक विस्तार रहा, इस लाइव स्ट्रीमिंग को कुल 23 देशों में देखा गया और भारत वर्ष में सभी प्रदेशों में देखा गया।

Day 1: 10 दिसंबर 2020

1. सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक कुमार ने विभागीय योजनाओं पर प्रकाश डाला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक कुमार ने कहा कि उद्योगों में निवेश को आकर्षित करने के लिए परिवहन और ढांचागत व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा रही है। ढेर सारी नीतियां पाइपलाइन में हैं।

2. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुरेश आर. बी. रेड्डी ने कहा कि गन्ना उद्योगों के क्षेत्र में खराब पानी प्रबंधन की कमी से गन्ना उद्योगों में बड़ी समस्याएँ आई हैं। गन्ना उद्योग के विकास के लिए बड़े पैमाने पर उपकरण और मशीनें वितरित की गई हैं। गन्ना बीज विकास के लिए महिला किसानों के समर्थन की दिशा में महिला विकास के लिए निवेश किया गया है।
3. यूपीसीएसआर के डायरेक्टर डा. जे सिंह ने कहा कि गन्ना की खेती के दौरान आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला। कहा कि समाजिक और आर्थिक समस्याओं के साथ आधुनिक तकनीक से महारूम किसान गन्ने की अच्छी फसल उगाने से वंचित रह जाते हैं।
4. जल शक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह ने कहा है कि जल का संरक्षण समय की मांग है। वर्षा जल संचयन के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही कानून लाएगी। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए हर घर नल योजना शुरू हो चुकी। शीघ्र ही पूर्वांचल सहित अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार होगा। जल शक्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव टी वेंकटेश ने जल संसाधन प्रबंधन, चुनौतियाँ व समाधान विषय पर वक्तव्य दिया।
5. सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स की वर्तमान स्थिति विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मुख्य सचिव श्री आलोक कुमार ने विभागीय योजनाओं पर प्रकाश डाला पर एम.एन.आई.टी. प्रयागराज के प्रो. वी.एस. त्रिपाठी ने पूर्वांचल में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में अवसरों एवं क्षमताओं के सन्दर्भ में मुद्दों एवं चुनौतियों को व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत किया।
6. विनिर्माण क्षेत्र की अध्यक्षता औद्योगिक विभाग के मंत्री सतीश महाना ने की। मुख्य वक्ता एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक कुमार ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि पर आधारित है। अधिकांश लोगों की आय कृषि और उससे संबंधित उद्योगों पर निर्भर करती है। मणिपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. ए.पी. पाण्डेय ने कहा कि पूर्वी यूपी. में हथकरघा उत्पाद सबसे बड़े और सबसे अमीर और असंगठित हथकरघा उद्योग बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार के श्रोत उपलब्ध कराता था, वर्तमान में इसकी स्थिति दयनीय हुई है।
7. प्राइमरी सेक्टर की अध्यक्षता गन्ना विकास चीनी मील एवं औद्योगिक विकास मंत्री श्री सुरेश राणा ने की। मुख्य वक्ता एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री सुरेश आर. बी. रेड्डी ने कहा कि गन्ना उद्योग के क्षेत्र में खराब पानी प्रबंधन की कमी से गन्ना उद्योगों में बड़ी समस्याएँ आई हैं। गन्ना उद्योग के विकास के लिए बड़े पैमाने पर उपकरण और मशीनें वितरित की गई हैं।

Day 2: 11 दिसंबर 2020

1. बैंकर्स मीट में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पूर्वांचल विकास के पथ पर अग्रसर है। योगी सरकार की ओर से क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने बैंकों को जन-धन विकास निधि के समानुपातिक उपयोग करने पर बल दिया। साथ ही बैंकिंग क्षेत्रों से आग्रह किया कि पूर्वांचल के विकास के लिए न्यूनतम 40 हजार करोड़ की व्यवस्था की जाए।

2. इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने कहा कि पूर्वांचल के विकास में बैंकर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बैंकर्स से आग्रह किया कि पूर्वांचल के अधिकांश किसान छोटे एवं सिमांत किसान हैं। जिन्हें छोटी धनराशि की आवश्यकता होती। उन्होंने बैंकर्स से आग्रह किया कि किसानों को आसानी से लोन दें।
3. खादी ग्रामोद्योग मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश खासकर ग्रामीण विकास के लिए एक सही मॉडल बनाया जायेगा। अपर मुख्य सचिव, श्री नवनीत सहगल जी ने कहा कि क्षेत्रीय कलाओं को कौशल विकास से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने अध्यक्षता करते हुए पूर्वांचल को मछली उत्पादन का हब बनाने की बात कही।
4. एक और सत्र की अध्यक्षता करते हुए डॉ. महेन्द्र सिंह जी, जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जल खर्च पर निगरानी करने के लिए सरकार एक व्यवस्था बनायेगी। जल पर चर्चा करते हुए अनेक परियोजनाओं को इससे जोड़ने की बात कही। जल उत्पादन पर काम करने की बात कही, इसके लिए सतत जल प्रबन्धन पर मंथन किया।
5. कृषि मंत्री ने एक सत्र की अध्यक्षता करते हुए इस बात पर चर्चा की कि पिछले तीन सालों में 300 करोड़ रुपये कृषि विज्ञान केन्द्र एवं अन्य संस्थानों पर किया गया है। इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जायेगा। कृषि मंत्री ने इस बात पर भी चर्चा की कि 20 लाख किसानों को सरकार मुफ्त बीज देगी।
6. एक सत्र में बोलते हुए डॉ. तनवीर आलम, भारत पैकेजिंग संस्थान के निदेशक पैकेजिंग उद्योग की व्यवस्था फूड प्रोसेसिंग एवं एग्रो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट से जोड़ने की बात कही और सरकार से अनुरोध किया कि इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करना चाहिए। श्री नवनीत सहगल जी इस बात की चर्चा की कि पूर्वांचल को अर्थव्यवस्था का नया हब बनाया जायेगा।
7. नवनीत कुमार सहगल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, एमएसएमई, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ने ओडीओपी के क्षेत्र और योजनाओं में किए जा रहे प्रमुख कार्यों पर जोर दिया और बड़े पैमाने पर उत्पादन और गुणवत्ता की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया और इसके लिए उन्होंने संबंधित तकनीकी सहायता और मशीनरी की मांग की। ज्ञान।
8. प्रोफेसर राम चेत चौधरी, अध्यक्ष, पीआरडीएफ, कृषि वैज्ञानिक, गोरखपुर ने जैविक कलानमक चावल के लगातार उत्पादन और इससे होने वाले मुनाफे के बारे में चर्चा की। उन्होंने कलानमक चावल उत्पादन में मजदूरों के बड़े पैमाने पर रोजगार का उल्लेख किया।
9. डॉ. अंबरीश गौड़, फैशन डिज़ाइन विभाग, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर ने मरने वाले शिल्प को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता का वर्णन किया और पूर्वांचल के लिए वन ब्रांड और वन आइडेंटिटी पर जोर दिया और स्थानीय प्रस्तुतियों के लिए वैश्विक मंच प्रदान करने की बात की। उमेश कुमार प्रजापति, टेराकोटा कारीगर ने ध्यान केंद्रित किया। पैकेजिंग कौशल और उनके टेराकोटा आइटम के लिए सामग्री को विभिन्न स्थलों तक ऑनलाइन पहुंचाने की आवश्यकता पर। श्री रवि प्रसाद, केले फाइबर हैंडीक्राफ्ट

उद्यमी, कुशीनगर ने कौशल स्थानीय लोगों की कमी पर चर्चा की, जो केले के पेड़ को कचरे के रूप में उपयोग करते हैं।

10. जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि जल्द ही प्रदेश को नई जल नीति की सौगात मिल जाएगी। नई जल नीति में घर से लेकर खेत तक और आद्योगिक संस्थानों पर पानी के खर्च की निगरानी और संरक्षण के नियम निर्धारित होंगे।
11. माननीय राज्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण श्री अतुल गर्ग जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हुआ है, 10 नए मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। संक्रामक रोगों से बच्चों की मृत्यु में 90% की कमी आयी है। श्री गर्ग ने कहा कि चिकित्सा संस्थाओं द्वारा बनाए गए रूल्स एवं रेगुलेशन इतने कठिन हैं कि वह प्रोत्साहित करने की जगह हतोत्साहित करते हैं। नियम एवं कानून भारत एवं यहां की परिस्थितियों के हिसाब से होना चाहिए। डॉ. एन.सी. प्रजापति, डीजी मेडिकल हेल्थ ने कहा कि पूर्वांचल में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नित नए परिवर्तन हो रहे हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कई चरणों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। शीघ्र ही पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की यू.जी. एवं पी.जी. सीटों में बढ़ोतरी के साथ नए मेडिकल, डेंटल एवं नर्सिंग कालेजों की स्थापना होगी। उन्होंने डब्ल्यू.एच.ओ. के दिशा-निर्देशों के अनुसार डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता पर चर्चा की।
12. समाज कल्याण तथा पूर्वांचल क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन की संभावनाएं एवं उच्च शिक्षा के विकास पर माननीय कैबिनेट मंत्री, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश श्री रमापति शास्त्री ने पूर्वांचल के लोगों से जुड़े कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पर भी चर्चा किया। प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने कहा कि नेपाल सीमा के पास 15 लाख आदिवासी लोग रहते हैं जो हाशिए पर थे और राज्य सरकार ने अपनी प्रभावी और दूरदर्शी योजनाओं और नीतियों के साथ इन आदिवासी लोगों के जीवन को सुरक्षा प्रदान करने तथा जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।
13. कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने अध्यक्षीय उद्घोषण में पूर्वांचल के सतत विकास के लिए किसानों को उपज बढ़ाने हेतु आधुनिक तकनीक पर आधारित किसी विधियों को अपनाने पर बल दिया उन्होंने बताया कि घरेलू कृषि उत्पाद की जरूरत की आपूर्ति एवं निर्यात के बीच एक समन्वय बनाना होगा जिससे किसान के उत्पाद की मार्केट वैल्यू कम ना हो माननीय मंत्री जी ने सरकार द्वारा भंडारण को बढ़ाने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने की वचनबद्धता को दोहराया। उन्होंने प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने तथा आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए सस्ती टेक्नोलॉजी मुहैया कराने, उर्वरक एवं शीलता बीज प्रदान करने की आवश्यकता सहकारिता समूह द्वारा बताई। मंत्री जी ने प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शुरू की गई आत्म निर्भर भारत योजना का अधिक से अधिक लाभ किसानों तक पहुंचाने एवं उनकी खुशहाली के लिए किए गए संयुक्त प्रयोजनों की सराहना की। मंत्री जी ने प्रदेश में हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों के विकास पर बल दिया साथ ही साथ सभी के समक्ष इस बात को रखा कि श्री योगी

आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फसली बीमा योजना का विस्तार जिला स्तर पर उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से हुआ है।

14. डॉ देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव कृषि विभाग ने कोरोना काल में कृषि के महत्व को रेखांकित करते हुए कृषि क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशने के विकास पर बल दिया। डॉक्टर चतुर्वेदी ने सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश की जलवायु, श्रम की उपलब्धता, प्रदेश में जल की उपलब्धता तथा बाजार तक उच्च पहुंच को प्रदेश के सकारात्मक पक्ष बताया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जोतो के आकार का छोटा होना तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में साख की कम उपलब्धता होना कृषिगत विकास में प्रमुख बाधक है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में मंडियों तथा सहकारी ढांचे को कृषि के परिपेक्ष में मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कृषि विविधता, जैविक खेती तथा एफ पी ओ को प्रदेश के कृषिगत विकास की संभावनाएं बताया। उन्होंने कृषि उत्पादन संगठनों (एफ पी ओ) की पॉलिसी, राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सहयोग की अपील की तथा फसल बीमा की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उसके बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया।
15. डॉक्टर जगदीश सिंह, उप निदेशक, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, ने सब्जियों के आर्थिक और पोषण शक्ति के दोहन पर बल देते हुए अपने वक्तव्य में बागवानी क्षेत्र, बागवानी उत्पादकता और बागवानी उत्पादन के विकास के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। डॉ सिंह ने बागवानी को ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी हटाने हेतु एक आर्थिक अवसर के रूप में विकसित करने पर बल दिया।
16. फ्रैंक इस्लाम, अध्यक्ष, एफ.आई. इन्वेस्टमेंट ग्रुप, अमेरिका ने पूर्वांचल में निवेश की अनेक संभावनाएं बताते हुए कहा कि पूर्वांचल दुनिया का सबसे उर्वर भूमि वाला क्षेत्र है, इसके उपयोग की दशा और दिशा को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। फ्रैंक इस्लाम ने कृषि-निवेश पर बल देने की जरूरत बताई।
17. खादी और ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हमें पूर्वी यूपी के विकास में खासकर ग्रामीण आबादी के लिए एक स्थायी मॉडल की आवश्यकता है। सरकार के प्रयास से सड़क, विकास और हवाई अड्डे के लिए कनेक्टिविटी में सुधार किया जा रहा है। इस क्षेत्र में जापानी इंसेफलाइटिस को अत्यधिक नियंत्रित किया गया है। 14 खादी उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं और वे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ बंधे हैं। उन्होंने शोधकर्ताओं और उद्यमियों पर जोर दिया: मुझे समाधान दो, मैं तुम्हें रास्ते दे दूंगा।
18. पूर्वांचल में लघु और मध्यम पैमाने के उद्योगों की स्थिति और विकास विषय पर खादी ग्रामोद्योग के एडिशनल सेक्रेटरी नवनीत सहगल ने कहा कि हमें अपनी खुद की कलाओं और टेराकोटा जैसे कौशल को जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। गुजरात डेयरी के मॉडल का उपयोग करके इसे बाजार से जोड़ना चाहिए।
19. लघु, मध्यम उद्योग राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने कहा कि पूर्वांचल में कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प की बेहद समृद्ध परंपरा रही है। मुख्यमंत्री जी इसके लिये लगातार प्रयासरत हैं कि किस तरह ODOP को ज्यादा से ज्यादा रोजगार का प्लेटफॉर्म बनाया जाए।

20. MSME और निर्यात संवर्द्धन विभाग के मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल लघु एवं मध्यम उद्योग के विकास और इन उद्योगों के उत्पादों के निर्यात के लिए विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रमों तथा भविष्य के रोडमैप को प्रस्तुत किया। उन्होंने पूर्वांचल विकास के लिए ODOP योजना को महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए एक जिला एक उत्पाद पर जोर दिया तथा बताया कि इस सन्दर्भ में अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें मुख्य रूप से मार्जिनल मनी स्कीम और टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वांचल के विकास पर जोर दिया जा रहा है।
21. विकलांग सशक्तिकरण पर चर्चा करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश श्री हेमंतराव ने अपने संबोधन में विकलांगों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विकलांगों को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न वित्तीय सहायता / सुविधाएं प्रदान की गई हैं। विकलांगों से संबंधित मुद्दे नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच ध्यान के केंद्र में हैं। विभाग विकलांग लोगों को तकनीकी सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए भी काम कर रहा है ताकि उनका दिन-प्रतिदिन का जीवन आसान हो सके। ये उपकरण विकलांग लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद करेंगे।
22. बेसिक और माध्यमिक शिक्षा सत्र में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि शिक्षा और विकास से संबंधित जानकारी सरकारी अधिकारियों को अच्छी तरह से बताई गई है और वे आवश्यकता के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पहले कोई एकीकृत प्रयास नहीं किए जा रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पर भी चर्चा की।
23. बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश के महानिदेशक श्री विजय किरणानंद ने उल्लेख किया कि किसी भी देश का विकास शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश पर निर्भर करता है। COVID-19 महामारी के बाद खुलने पर हमें स्कूलों में दी जाने वाली सुविधाओं को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य को ठीक करना होगा और इसे कदम से कदम मिलाने की कोशिश करनी होगी। हमें स्मार्ट क्लासेस सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए और छात्रों को सकारात्मक माहौल देने की कोशिश करनी चाहिए।
24. स्पेशल पैकेज फॉर पूर्वांचल विषयक विशेष सत्र की अध्यक्षता लोक निर्माण विभाग राज्यमंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने की। मुख्य वक्ता प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन गोकर्ण ने कहा विभागीय योजनाओं का लेखा जोखा पेश किया। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने रेलवे की पूर्वांचल में केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं की चर्चा करते हुए पूर्वांचल के विकास हेतु इसे आधार के रूप में प्रस्तुत किया।
25. प्रो. राकेश सिंह, अध्यक्ष, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जॉर्जिया विश्वविद्यालय ने खाद्य प्रौद्योगिकी और पैकेजिंग में नई तकनीकों के बारे में बात की। डॉ. सिंह ने खाद्य उद्योगों में मिलने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा की जैसे कि ताजे फल और सब्जियों की उच्च मांग और अल्पावधि खाद्य भंडारण में सुधार की आवश्यकता। उन्होंने हमें यूएसए की विभिन्न खाद्य सुरक्षा विनियमन एजेंसियों के बारे में बताया। भारत में प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला में कुछ मुद्दे और चुनौतियां जैसे मूल्य वृद्धि, कम जीवन आदि हैं। खाद्य तकनीक में आधुनिक तकनीकों और प्रसंस्करण तकनीक के बारे में बताया जैसे कि फ्रीज ड्राई, और केचप

और जैम के लिए हॉट फिल ऑपरेशन, बेवरेज और सॉस के प्रसंस्करण, सड़न रोकने वाला प्रसंस्करण प्रणाली, मूंगफली में निरंतर प्रवाह उच्च दबाव प्रणाली अफलातून कमी।

26. भारत सरकार के पैकेजिंग संस्थान के निदेशक डॉ. तनवीर आलम ने कहा कि पूर्वी यूपी में विकास और खाद्य पैकेजिंग उद्योग की संभावना के बारे में उत्तर प्रदेश में भारत में कुल दूध का 16.9% उत्पादन होता है और भारत में सबसे अच्छा राज्य है। यूपी भी 20.25% मांस का उत्पादन करता है और भारत में सबसे अच्छी जगह रखता है लेकिन केवल 2.19% अंडे का उत्पादन करता है। उन्होंने बताया कि उच्च दूध उत्पादन के बावजूद, इसका उपलब्ध / प्रति व्यक्ति / दिन दूध का केवल 44% है। मुख्य मुद्दे गायों और भैंसों की बांझपन, हरे चारे की अपर्याप्त उपलब्धता और कम टीकाकरण दर, कौशल और उद्यमशीलता की कमी है। कुक्कुटों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे कि गुणवत्ता वाले रोगाणु प्लाज्मा की कम उपलब्धता और पशुधन और मुर्गी पालन और खराब फसल कटाई प्रबंधन।
27. नाबार्ड, लखनऊ के डॉ. विवेक पठानिया ने डेयरी पर लघु और सीमांत किसानों के लिए सतत आजीविका के रूप में चर्चा की। उन्होंने हमें सूचित किया कि यूपी दूध का उच्चतम उत्पादक है यानी 16% है, लेकिन इसमें कम पशु उत्पादकता / औसत उपज / किग्रा / दिन है। फ्रीड और चारे की कमी, पर्याप्त प्रजनन और स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे की कमी हैं। पशु चिकित्सालयों की भारी कमी है। यूपी के पांच शीर्ष दूध उत्पादन जिले जौनपुर, गोंडा, बहराइच, आजमगढ़ और इलाहाबाद हैं, लेकिन अभी भी राज्य की दूध की मांग पूरी नहीं हुई है। केवल 20% दूध ही डायरियों से गुजरा है और केवल दूध ही प्रमुख प्रसंस्कृत उत्पाद है। वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने डेयरी स्थिरता के लिए कुछ समाधान सुझाए जैसे कि पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि और विपणन योग्य अधिशेष, प्रजनन और स्वास्थ्य सेवा में सुधार, संगठित दूध प्रसंस्करण के लिए अधिक पहुंच, बुनियादी ढांचे में सुधार आदि नए समृद्ध फ्रीड और अज़ोला और सिलेज जैसे चारा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
28. माननीय मंत्री श्री विजय कश्यप, राज्य मंत्री, राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण उत्तर प्रदेश, सरकार ने किया। परिचर्चा का मुख्य बिंदु पूर्वांचल क्षेत्र से सम्बंधित बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन से सम्बंधित विषयों पर चर्चा हुई। प्रथम वक्ता के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) आर पी शाही, वॉइस चेयरमैन उत्तर प्रदेश राज्य, आपदा प्रबंधन ने अपने विचार पूर्वांचल क्षेत्र की बाढ़ समस्या, उसके संभावित निदान तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों पर व्यक्त किये।
29. सीएसआईआर के सहायक निदेशक डा. शेखर सी पांडेय ने कहा कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक मेथेनाल का उत्पादन देश के अंदर होता है। देश में मेथेनाल के उत्पादन का 80 फीसदी सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है। इनमें से भी दो तिहाई से अधिक उत्पादन पूर्वी यूपी में हो रहा है। इससे जुड़े उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित किया जा सकता है
30. श्री लाखन सिंह राजपूत, राज्य के कृषि, कृषि शिक्षा और अनुसंधान मंत्री ने की। मुख्य विषय फसल विविधीकरण था और पूर्वी यूपी में विभिन्न तरीकों से फसल उत्पादन को बढ़ावा देना था। पूर्वी यूपी के विकास में कृषि ने बहुत योगदान दिया है और यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेगा। धान और गेहूं के लिए उच्च पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जैसे कि लगभग 16 किग्रा नाइट्रोजन / हेक्टेयर। जैविक खेती के

दौरान इस मांग को पूरा करने के लिए 30 टन / हेक्टेयर गोबर खाद की आवश्यकता होगी। जैविक खेती के दौरान फसल की उपज में धीमी वृद्धि किसानों के लिए भी एक भय है। इस प्रकार यह उनकी स्थानीय भाषा में उचित जागरूकता की आवश्यकता है और इस उद्देश्य के लिए कृषि मेला आयोजित किया जाना चाहिए।

31. पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश उद्यम विकास केन्द्र और राष्ट्र सरकार के उद्यम विकास संस्थान गाँधी नगर, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में उद्यमी विकास केन्द्र की स्थापना होगी।
32. पूर्वी उत्तर प्रदेश में युवा जनता को बहुसंख्या में अच्छे उद्योग दिलाने के लिए आवश्यक कौशल विकास का प्रयत्न किया जा रहा है। इस संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में एक कौशल विकास केन्द्र की रचना की जायेगी। इसमें भारत सरकार, शासन और कौशल विकास केन्द्र की सहायता ली जायेगी।
33. पूर्वी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में एक विशेष विकास अध्ययन केन्द्र रचित किया जायेगा। इसमें स्नातकोत्तर विद्यार्थी और पी.एच.डी. विद्यार्थियों को विशेष रूप से फेलोशिप दिया जायेगा। उसके लिए दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ने 50 लाख रुपये की राशि प्रतिवर्ष की व्यवस्था की है, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार शासन ने 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष के आधार पर तीन वर्षों में सहायता देना आवश्यक है। इस आधार पर फेलोशिप की सहायता से पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख समस्याओं पर शोध कार्य करने में सहयोग होगा।